ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4
बर्बाद कर दिया गया सालो भर जल देने वाला रातूरोड रांची का कुंआ

रविवारीय, 18 - 24 अक्टूबर 2020 वर्ष- दो, अंक-11, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।
greenrevolt2019@gmail.com
9798166006

प्लास्टिक अपशिष्ट और ईपीआर के मामले में पर्यावरण मंत्रालय को मिले आम जनता के सुझाव

पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (पीडब्लूएम नियम), 2016 के तहत उत्पादकों की जिम्मेवारी (ईपीआर) को तय करने से जुड़े फ्रेमवर्क के लिए आम जनता से उनके विचार मांगे थे। इस मामले में विभिन्न संगठनों और लोगों से करीब 160 टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।

यह टिप्पणियां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, अपशिष्ट प्रबंधन पर काम कर रहे संस्थानों, उद्योग, उद्योग संघों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों से प्राप्त हुई हैं। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इन टिप्पणियों का संकलन और समीक्षा की जा रही हैं। बाद में जिसका उपयोग ईपीआर फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने के लिए किया जाएगा। यह जानकारी अवनि मिश्रा बनाम भारत संघ (मूल आवेदन संख्या 29/2020) के मामले में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सबमिट रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट को 12 अक्टूबर, 2020 को एनजीटी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

एतिहासिक व प्रागैतिहासिक स्थलों से समृद्ध राज्य, इंद्रजालिक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जहां पर्यटन के एक रोजगारपरक उद्योग बनने की अपार संभावनायें दिखती हैं, पर अपने

अमूल्य धरोहरों के प्रति लापरवाह है झारखंड

मनोज कुमार शर्मा

विश्व में कई देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था सिर्फ पर्यटन से ही चलती है। यूरोप का स्वीट्जरलैंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे देश में गोआ की अर्थव्यवस्था में भी सबसे बड़ा हिस्सा पर्यटन का ही है।

झारखंड को अगर हम गौर से देखें तो हमारा राज्य सिर्फ खनिज संपदा के मामले में ही समृद्ध नहीं है बल्कि प्राकृतिक सुंदरता और एतिहासिक, प्रागैतिहासिक स्थलों से भी परिपूर्ण है। लंबे समय तक झारखंड का यह सौंदर्य बाहरी लोगों के नजरों से ओझल रहा। किताबों में भी सिर्फ हुंडरू या अन्य गिने चुने जलप्रपातों का उल्लेख मिलते रहा, पर राज्य बनने के बाद झारखंड की खुबसूरती धीरे-धीरे सबों के सामने आयी। देश विदेश के नेताओं और लोगों ने जब झारखंड को करीब से देखा तो वह यहां की खुबसूरती देख कर मंत्रमुग्ध से हो गये, पर उन्हें इस बात का दुखद आश्चर्य भी हुआ कि इतना खुबसूरत राज्य जो सिर्फ पर्यटन से भी समृद्ध हो सकता है वह पलायन झेल रहा है और वह पर्यटन के मानचित्र पर कहीं नहीं दिखता।

झारखंड के जाने माने पर्यावरणविद् और भूगर्भविज्ञानी डॉ. नितिश प्रियदर्शी का कहना है कि झारखंड की भूमि हिमालय से भी करोड़ो वर्ष पुरानी है और यहां प्रागैतिहासिक काल के बहुत सारे स्थल हैं। जहां ऐसे इक्के दुक्के स्थल अन्य राज्यों में हैं वहां इस पर शोध हो रहे हैं और इसे प्रचारित भी किया जा रहा है, पर झारखंड स्वयं अपने इन अमूल्य धरोहरों से अनभिज्ञ है और ये धरोहर बर्बाद हो रहे हैं।

अगर आप झारखंड के अंदरूनी हिस्सों में घूमें तो कई ऐसी अप्रत्याशित चीजें दिख जायेंगी जो अमूल्य हैं, पर उनका संरक्षण तो दूर की बात है वहां सर्वत्र ऊंचे विशाल पहाड़ियों को दैत्याकार मशीनों से काट कर उसके पत्थरों को बेचने का धंधा चालू है। सरकारें आती जाती हैं, किसी खास पर्यटन स्थल पर महोत्सव करवा कर बैनर होर्डिंग तो लगा जाती हैं, पर इन स्थलों को बर्बाद होने से बचाने की कोशिश किसी ने नहीं की।

दूमका के टेराकोट से बने मलूटी मंदिर

रांची पहाड़ी के सीने पर झंडे के लिये बनाया गया खंभा

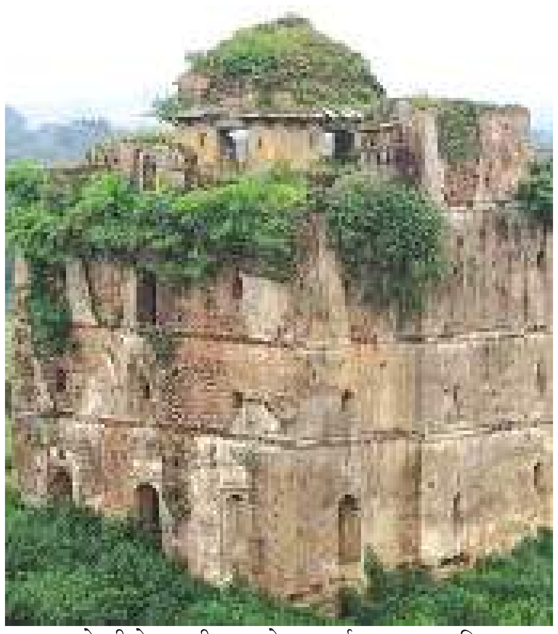

अपने जीणोद्धार की बाट जोहता जर्जर नवरत्नगढ किला

रांची पहाड़ी का हाल बेहाल

क्या कभी आपने ऐसा सोंचा है कि ऐसे कितने शहर होंगे जिसके बीचो बीच कोई रमणिक हरी भरी पहाड़ी हो और जिसकी चोटी से हम पूरे शहरा का नयनाभिराम अवलोकन कर सकें? रांची इस मायने में अप्रतिम है। शहर के बीच में रांची पहाड़ी है जिसे रिची बुरू और फांसी टुंगरी नाम से भी जाना जाता है। इस पहाड़ी की चोटी से पूरे शहर का अवलोकन किया जा सकता है, यह पहाड़ी हिमालय से भी पुरानी है और खोंडोलाइट चट्टानों की बनी हुइ है, पर इसका संरक्षण तो दूर इसे धंसाने और बर्बाद करने का काम अनवरत जारी है। कभी आस्था के नाम पर , कभी संवारने के नाम पर , कभी देश के सबसे बड़े तिरंगे को फहराने के नाम पर इस खुबसूरत पहाड़ी के साथ शहरवासियों से लेकर, सरकार तक ने सिर्फ क्षति पहुंचायी है?

मलूटी का गुप्तकाशी

मलूटी झारखण्ड राज्य के दुमका जिले में शिकारीपाड़ा के निकट एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ 72 पुराने मंदिर हैं जो बज बसन्त वंश के राज्यकाल में बने थे। इन मन्दिरों में रामायण तथा महाभारत और अन्य हिन्दू ग्रन्थों की विविध कथाओं के दृष्यों का चित्रण है। ये मंदिर टेराकोटा यानि मिट्टी से ही बने हुये हैं। लंबे समय तक इनके संरक्षण की मांग होती रही और कुछ साल पहले इन मंदिरों के संरक्षण का काम किया गया। अब जानकारों का कहना है कि गलत संरक्षण के कारण इन मंदिरों का मूल स्वरूप ही खत्म कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अब इन मंदिरों के दिवारों पर संरक्षण के नाम पर टाइल्स चिपका दिये गये हैं। प्रारंभ में भी कुछ जानकारों ने यहां दिवारों पर टाइल्स लगाने के काम पर आपति जतायी थी।

नवरत्न गढ़

गुमला के सिसई में 17वीं शताब्दी में बनाया गया नवरत्नगढ का किला किसी अजूबे से कम नहीं है। नागवंशी राजाओं की यह नगरी चारो ओर पहाड़ों और चट्टानों से घिरी हुई है जो किसी प्राकृतिक किले का काम करते हैं। कहते हैं कि नागवंशी राजा दुर्जनशाल ने मुगल शासक जहांगीर की कैद से छूटने के बाद यहां इस नगर को बसाया था। इसे डोइसागढ भी कहते हैं। यहां कभी नौमंजिली इमारतें भी हुआ करती थीं और पत्थरों को काट कर एवं हस्तनिर्मित इटों से महल, मंदिर और दरबार बनाये गये थे। जब इसका पुरातात्विक महत्व समझ में आया तो इसे यूनेस्कों की धरोहरों में शामिल तो कर लिया गया, पर इसके संरक्षण का अब तक कोई काम नहीं हुआ है। शोध हों तो यहां की पहाड़ियां भी कई रोचक राज छुपायें हुये मिलेंगी?

पहाड़ों को काट कर बेचने का जुनून

झारखंड का मूल सौंदर्य यहां के जंगलों और उनमें स्थित पहाड़ियां है। लेकिन ये सबसे दुखद बात है कि झारखंड कि किसी भी जिले में चले जायें वहां यह देख सकते है कि क्रशर उद्योग विशाल खुबसूरत पहाड़ियों को लील रहे हैं। ग्रीन रिवोल्ट जब नवरत्नगढ जाकर इस पुरातात्विक महत्व के किले की जानकारी एकत्र कर रहा था तो वहां के सबसे बड़े पहाड़ की कटाई चालू थी, और उसका एक बड़ा हिस्सा क्रशर उद्योग की भेंट चढ चुका था। उस पहाड़ पर कई बड़ी मशीने लगी हुयीं थीं जो पत्थर काट और ढो रही थीं। क्रशर के लिये बेतहाशा पहाड़ियों की कटाई में कई ऐसे पहाड़ों को भी लुप्त कर दिया गया होगा जो एतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की रही होंगी। दुसरी बात की पहाड़ों का होना जल संरक्षण और पर्यावरण के लिये भी जरूरी है।

रांची रेलवे स्टेशन में फुट ओवर ब्रिज के गार्डर लॉन्चिंग का काम हुआ पूरा

रांची रेलवे स्टेशन रांची रेल मंडल का एक अति व्यस्त रेलवे स्टेशन है ,यहां प्रतिदिन हजारों रेल यात्रियों का आवागमन होता है। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, यात्री एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आसानी से आवागमन कर सके इसके लिए नए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है।

वर्तमान में रांची रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 01 से प्लेटफार्म नंबर 02 एवं 03 पर फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से जाया जा सकता है तथा प्लेटफार्म नंबर 04 एवं 05 पर जाने के लिए उस फुटओवर ब्रिज से दूसरे फुट ओवरब्रिज तक जाना होता है, लेकिन अब नए फुट ओवर ब्रिज के निर्माण से यात्री मुख्य प्रवेश द्वार के सर्कुलेटिंग एरिया (पार्किंग एरिया) से प्लेटफार्म नंबर 01, प्लेटफार्म नंबर 02 और 03, प्लेटफार्म नंबर 04 एवं 05 या स्टेशन के साउथ एंट्री गेट पर जा सकते हैं, तथा स्टेशन के साउथ इंट्री गेट से आने वाले यात्री इसी प्रकार किसी भी प्लेटफार्म में उस फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से पहुंच सकते हैं या फिर स्टेशन के नार्थ एंट्री गेट मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ निकल सकते हैं। इस फुट ओवर ब्रिज की चौड़ाई 20 फीट है तथा इसकी कुल लंबाई लगभग 100 मीटर होगी। इस फुट ओवर ब्रिज के निर्माण से वर्तमान में यात्रियों के लिए जो बाहर निकलने की सुविधा है वह भी उपलब्ध रहेगी तथा यात्री पार्किंग एरिया मैं भी फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से पहुंच सकते हैं।

इस फुट ओवरब्रिज के निर्माण हो जाने से यात्रियों को रांची रेलवे स्टेशन के किसी भी प्रवेश द्वार से किसी भी प्लेटफार्म पर जाने तथा आने के लिए के लिए सुविधा होगी । फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य मार्च 2021 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

13अक्टूबर को फुट ओवर ब्रिज निर्माण के कार्य के लिए सुबह 09:15 बजे से सायं 16:45 बजे तक साढ़े 07 घंटे का ब्लॉक लिया गया । जिसमें लगभग 50 फीट लंबाई के गार्डर लगाए (Girder Launching) गए हैं । इस महत्वपूर्ण ब्लॉक (गार्डर लॉन्चिंग) के में 250 कर्मचारी लगे हुये थे। इसमें अपर मंडल रेल प्रबंधक (इंफ्रा)अजीत सिंह यादव, वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय) अमित कंचन, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक नीरज कुमार, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता ए आर दास, मंडल अभियंता(दक्षिण) दीपक कुमार, कोचिंग डिपो अधिकारी राजीव रसिक एवं अन्य अधिकारी रांची रेलवे स्टेशन पर उपस्थित थे।

17अक्टूबर से रांची - हावड़ा के बीच प्रतिदिन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन

रांची : त्योहार के इस पर्व में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रांची - हावड़ा के बीच एक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन दिनांक 17अक्टूबर 2020से चल रही है।

● ट्रेन संख्या 02803 रांची - हावड़ा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन दिनांक 17/10/ 2020 से दिनांक 30/11/2020 तक (कुल 45 फेरे) चलेगी । रांची से प्रस्थान 21:30 बजे होगा, मुरी आगमन 22:55, प्रस्थान 23:15, टाटानगर आगमन 01:25, प्रस्थान 01:30,खड़ग पुर आगमन 03:15, प्रस्थान 03:20, हावड़ा आगमन 05:10 बजे होगा।

● ट्रेन संख्या 02804 हावड़ा - रांची फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन दिनांक 18/10/ 2020 से दिनांक 01/12/2020 तक(कुल 46 फेरे) चलेगी । हावड़ा से प्रस्थान 22:10 बजे, खड़कपुर आगमन 23:50, प्रस्थान 23:55, टाटा नगर आगमन 01:40, प्रस्थान 01:45, मुरी आगमन 04:05, प्रस्थान 04:25, रांची आगमन 05:50 बजे होगा।

इन ट्रेनों से यात्रा हेतु सीटों का आरक्षण हो रहा है।

बांका रेत खननः एनजीटी ने दिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश

एजेंसियांः एनजीटी ने 14 अक्टूबर को बिहार के बांका में रेत खनन पर एक ताजा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इस बाबत एनजीटी में दायर एक आवेदन के अनुसार बांका में रेत खनन के मामले पर 2018 में अंतरिम जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) तैयार की गई थी, लेकिन उसे आज तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है

इस नई डीएसआर रिपोर्ट को तैयार करने के लिए एनजीटी ने निर्देश दिया है कि इस डीएसआर को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग या क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त सलाहकारों के माध्यम से ही तैयार किया जाना चाहिए।

एनजीटी ने निर्देश दिया है कि इस डीएसआर को जिला मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना होगा, जो डीएसआर का जिले के भौतिक और भौगोलिक विशेषताओं से संबंधित तथ्यों के संबंध में सत्यापन करेंगे। सत्यापन के बाद जिला मजिस्ट्रेट इस रिपोर्ट को जांच के लिए राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के पास भेजेंगे यदि यह रिपोर्ट सभी वैज्ञानिक और तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करती है तो एसईएसी उसे राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास विचार और अनुमोदन के लिए भेजेंगे। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त सलाहकार या एजेंसी की भी मदद ली जाऐ जिसे एसएसएमएमजी 2016 और इएमजीएसएम 2020 के तहत निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए।

रोजगार | ग्रामीण तालाबों का उपयोग मछली पालन के लिए करें

आशीष कुमार

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी गांव में तालाब उपलब्ध है। यदि उनका स्वामित्व देखा जाए तो आप पाएंगे कि कुछ तालाब सरकारी तालाब हैं, कुछ तालाब सामुदायिक तालाब है और कुछ तालाब बहु स्वामित्व वाले तालाब हैं जिनके कई मालिक हैं और कुछ तालाब एकल स्वामित्व वाले हैं।

यदि गहन सर्वेक्षण किया जाए तो पाया जाएगा कि लगभग 40% तालाबों में मछली पालन नहीं हो रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। संभव है कि तालाब गांव में है परंतु उसके जो मालिक हैं वह अपने व्यवसाय या नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। ऐसा भी होता है कि तालाब के कई मालिक हैं जिनकी आपस में एकमत नहीं है और मछली का लाभ के बंटवारे को लेकर ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई तालाब का उपयोग मछली पालन के लिए नहीं कर रहा है। लगभग यही स्थिति सामुदायिक तालाबों में भी है। कहीं-कहीं जहां पंचायत के लोग जागरूक हैं वहां आपस में चंदा करके मछली के बीज को तालाब में संचय करते हैं और जो भी मछलियां निकलती है उसे पूरे गांव में बांट लेते हैं।

कहीं-कहीं किसी विशेष प्रयोजन के लिए जैसे गांव में किसी सामाजिक कार्य जैसे स्कूल के भवन की मरम्मती, सड़क निर्माण अथवा किसी सांस्कृतिक कार्य के प्रयोजन से भी मछली पालन किया जाता है और उसके लाभ का उपयोग उन कार्यों में किया जाता है। परंतु अभी भी बड़ी संख्या में तालाब मछली पालन से वंचित है। ऐसे में यदि ग्रामीण युवक विशेष करके वैसे प्रवासी युवक जो बाहर से वापस आए हैं उनके लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर है।

सरकार के मत्स्य विभाग के द्वारा मत्स्य पालन में न केवल प्रशिक्षण दिया जाता है बल्कि मत्स्य बीज, मछली का दाना और जाल की आपूर्ति करके भी सहायता प्रदान की जाती है।

हम सभी जानते हैं कि मछली से ना केवल पौष्टिक आहार प्राप्त होता है बल्कि इसकी बिक्री से आर्थिक लाभ भी होता है। ऐसे में इस अवसर को पहचान कर ग्रामीण बेरोजगार नवयुवक अकेले अथवा एक समूह बनाकर यदि उनके गांव में बिना उपयोग के तालाब उपलब्ध हैं तो निश्चित रूप से उन्हें उन में मछली पालन करना चाहिए। इससे गांव के लोगों को ताजी मछली मिलेगी और उन्हें रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कभी-कभी किसान भाई इस बात से चिंतित हो जाते हैं कि उन्हें जो तालाब मिला है वह मौसमी है। ऐसी स्थिति में उन तालाबों का उपयोग मछली के बीज के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। मछली के बीज की भी बहुत अधिक मांग है जो अधिकांश बाहर से आते है। यदि स्थानीय स्तर पर बीज का उत्पादन हो तो उससे भी तालाबों में बीज के संचयन में सहायता मिलेगी और किसान को लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त यदि बांध पर जमीन उपलब्ध है तो उस पर मौसमी सब्जियों का उत्पादन करके अपने भोजन में पौष्टिक आहार की वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार तालाबों का उपयोग मछली पालन अथवा मछली बीज उत्पादन तथा साथ में सब्जी उत्पादन करके ना केवल इस संसाधन का उपयोग किया जा सकता है बल्कि स्थानीय स्तर पर ही रोजगार सृजित किया जा सकता है।

यदि क्षेत्र में कोई बेरोजगार नवयुवक आगे बढ़ना चाहते हैं तो तकनीकी सलाह के लिए लेखक से संपर्क कर सकते हैं।

लेखक सेवानिवृत उपनिदेशक (मत्स्य विभाग) हैं
Ph. 9430783037
email:oomar2012@gmail.com

देश की अधूरी तस्वीर

आइएमएफ ने भारत को दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे गरीब देश बनने की ओर अग्रसर बताया है। भारत से अच्छी स्थिति छोटे पड़ोसी देशों तक की बतायी गयी है। किसी भी सजग देशवासी को ये खबर मायूस और परेशान कर सकती है? बेशक कोरोना ने वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया है और भारत जैसा लुंजपुंज विशाल देश इसका बड़ा शिकार बना है। हमारी जीडीपी निगेटीव में चली गयी थी। ऐसा होना लाजमी था।

तो क्या सचमुच हम दक्षिण एशिया के कुछ गिने चुने गरीब देशों में से एक हैं? हकीकत ऐसा नहीं है। पिछले कुछ सालों में लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ है, गरीबी का पैमान भी अब बदल चुका है। गांव अब भूखे नंगो और लाचार लोगों की आबादी वाला इलाका नहीं रह गया है। आइएमएफ और विश्व बैंक के गरीबी मापने का जो मानदंड है वह अलग है वह भारत को भी उसी चश्मे से देखते हैं जो भारत पर फिट नहीं बैठता। देश के कुछ गिने चुने जगहों को छोड़ दें तो हकीकत में देश में लोग काम करने और अच्छी जीवन शैली को प्राप्त करने में लगे हुये हैं और ज्यादतर सफल हैं। कोरोना ने उसमें ब्रेक अवश्य लगाया है, पर यह ब्रेक क्षणिक है। अनलॉक के शुरू होते ही जैसे ही कारोबार में कुछ तेजी आयी अर्थव्यवस्था में भी एकाएक सुधार आया है।

भारत के महानगरों में कार्यरत ज्यादतर लोगों का जड़ अपने गावों से जुड़ा हुआ है। शहरों में वह अच्छी सुख सुविधा वाली जिंदगी और नगद कमाने के लिये गया हुआ है। किसी बुरी परिस्थिति में वह गांव लौट कर खेती कर जीवनयापन कर सकता है, वहीं भूमिहीन व्यक्ति भी गांवों में जाकर भारतीय सामाजिक ताने बाने में स्वरोजगार खोज लेता है। यही कारण है कि लॉकडाउन में सभी अपने गांव जाने को आतुर थे।

नेपाल, बांग्लादेश से लाखो लोग भारत में आकर वैध अवैध तरीके से रोजगार प्राप्त करते हैं। विश्व बैंक और आइएमएफ के लिये इसे समझना मुश्किल है। उनके लिये गरीबी और भूखमरी का पैमाना कुछ और है, ऐसे में भारत को दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे गरीब देश बता देना पूरी तरह से सच नहीं है। कुछेक पिछड़े इलाकों के दु:खद वाकयों से पेश भारत की यह भूखी नंगी तस्वीर पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती। इसका सबूत अभी पर्व त्यौहारों के मौसम में भारतीयों के क्रय शक्ति से मिल जायेगा।

हम सभी ये अवश्य ये उम्मीद कर सकते हैं कि खरीफ फसलों की कटाई और कोरोना की समाप्ति के बाद देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर होगी। हमें ये भी स्वीकार करना होगा कि भारत जैसे विशाल अर्द्धविकसित देश में सब कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता। आपदा, मंदी, महामारी से यहां हालात तेजी से बिगड़ते हैं तो अपार जीजीविषा वाला यह देश तेजी से उनसे उबरने की क्षमता भी रखता है। विश्वबैंक, विश्व और आइएमएफ भारत की इस शक्ति को आंकने में पहले भी चूक करते रहे हैं।

साभार इंडिया टूडे

संयुक्त राष्ट्र:पिछले 20 सालों में प्राकृतिक आपदाओं में तेज वृद्धि, एशिया सबसे ज्यादा प्रभावित

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पिछले 20 सालों में प्राकृतिक आपदाओं में तेज वृद्धि हुई है। जिसके कारण जान और माल का नुकसान तो ही रहा है बल्कि दुनिया भर में आर्थिक नुकसान भी हो रहा है।

संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पिछले 20 वर्षों में चरम मौसम की घटनाओं में नाटकीय रूप से बढ़ोतरी हुई है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोग मर रहे हैं और दुनिया भर में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूएन के मुताबिक एशिया सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुआ है। यूएन के मुताबिक चीन में (577) और अमेरिका में (467) सबसे अधिक आपदा की घटनाएं साल 2000 से लेकर 2019 तक दर्ज की गईं। इसके बाद भारत में 321, फिलीपींस में 304 और इंडोनेशिया में 278 आपदा से जुड़ी घटनाएं दर्ज की गईं।

संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के मौके पर इस रिपोर्ट को जारी किया है। शीर्ष के 10 देशों में से आठ देश एशिया में स्थित हैं। दुनिया में हर साल 13 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। दो दशक के दौरान 7,348 प्रमुख आपदा की घटनाओं को विश्व स्तर पर दर्ज किया गया। इन आपदाओं में दस लाख से अधिक लोगों की मौत हुई और 4.2 अरब लोग प्रभावित हुए। दो दशक के दौरान 2.97 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान भी दर्ज किया गया। बड़ी बाढ़ की संख्या दोगुनी होकर 3,254 हो गई। सूखा और जंगलों में आग लगने की घटनाओं ने भी कहर बरपाया। आपदा जोखिम कम करने के लिए यूएन महासचिव की विशेष प्रतिनिधि मामी मिजुटोरी के मुताबिक, "विस्तृत जलवायु आपातकाल से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं।" उन्होंने सरकारों से पूर्वानुमान चेतावनी में निवेश करने के साथ-साथ आपदा जोखिम कम करने की रणनीतियां अपनाने को कहा है। बेल्जियम के लौवेन यूनिवर्सिटी में आपदाओं की महामारी विज्ञान पर अनुसंधान केंद्र की देबारती गुहा-सापिर कहती हैं, "अगर चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि इसी तरह जारी रहता है तो अगले 20 सालों में इंसान का भविष्य बहुत अंधकारमय दिखता है।

भारतीय समुद्र तटों को मिला ब्लू टैग

एजेंसियां

भारत की छवि प्रदूषित और शोरगुल वाले शहरों की है। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खबर आयी है कि देश के 8 समुद्री तटों को सबसे साफ होने का ब्लू फ्लैग टैग मिला है।

एशिया में केवल ऐसे चार ही देश है जिनको समुद्री तट के लिए ब्लू फ्लैग टैग मिल सका है। यह खबर भारतीय समुद्री तटों के लिए किसी बड़े उपलब्धि से कम नहीं है जो दर्शाता है कि भारत के भी समुद्री तट विदेशी समुद्री तटों से कम नहीं है।

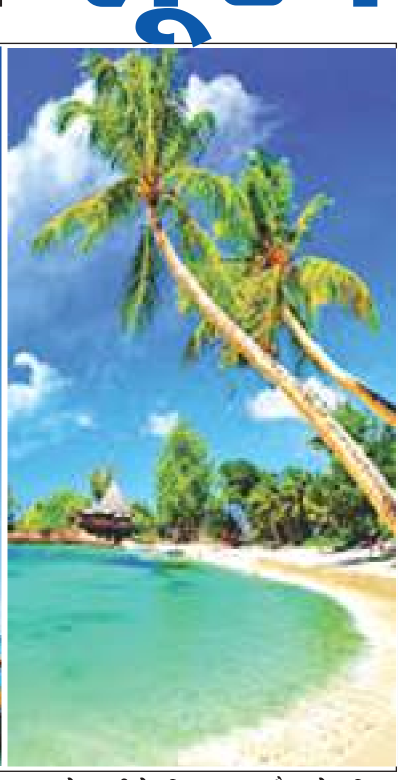

ब्लू फ्लैग टैग क्या है?

'ब्लू फ्लैग टैग' का मतलब होता है दुनिया के सबसे साफ-सुथरी और सुरक्षित समुद्री तट। इस टैग के साथ भारत उन पच्चास देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिन्हें ये टैग मिला हुआ है। इस टैग के मिलने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने भी ख़ुशी जजाते हुए ट्विट किया है और इसकी बधाई दी। 'फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन'ग्लोबल संस्था साफ-सुथरा और अन्य पहलू के मापदंडों को देखते हुए इस टैग को देती है। कहा जाता है कि इस टैग को देने के लिए लगभग 33 अलग-अलग मापदंडों को देखने के बाद इस टैग को दिया जाता है।

इन सात समुद्री तटो का मिला टैग?

शिवराजपुर बीच

ब्लू फ्लैग टैग की सूची में सबसे पहले शिवराजपुर बीच है, और ये बीच गुजरात के जामनगर में है। समुद्र प्रेमियों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। सफ़ेद बालू और नीले पानी के साथ ये बीच सैलानियों को काफी आनंदित करता है। इस बीच के आसपास घूमने के लिए भी बहुत कुछ है। यहां घूमने निकले तो प्रताप विलास पैलेस, खिजादिया पक्षी अभयारण्य और मरीन राष्ट्रीय उद्यान भी घूमने ज़रूर पहुंचें। यहां आप ट्रेन, बस या हवाई सफर के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं।

कप्पड़ बीच

कप्पड़ बीच दक्षिण भारत के केरल राज्य में है। केरल के सबसे खूबसूरत और शांत बीचेज में से एक माना जाता हैं। इस बीच के बारे में कहा जाता है कि इस बीच को र्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने 15 वीं शताब्दी के दौरान खोज की थी। बीच के साथ-साथ यहां घूमने के लिए कई डेस्टिनेशन है। पूकूट लेक, कप्पड बैकवाटर्स और कदलुंडी पक्षी अभयारण्य भी यहां घूमने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है। यहां पहुंचने के लिए आपको रेलवे स्टेशन, बस अड्डा या हवाई मार्ग से केरल आना होना और वहां से आपको लोकल गाड़ी कर के जा सकते हैं।

कासरकोड और पदुबिद्री बीच

ब्लू फ्लैग टैग पाने वाले समुद्री तट में कर्नाटक के दो बीच शामिल है। कर्नाटक में ये दोनों ही बीच सैलानियों के लिए प्रमुख स्थान है।

घोघ्ला बीच

प्रकृतिक की गोद में बसा ये बीच भारत के केंद्र शासित प्रदेश दमन एंड दीव में है। इस समुद्र तट की सुनहरी रेत, सूरज की रौशनी एक सम्मोहक दृश्य दिखाती है। घोघ्ला बीच को कई रोमांचक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। तैराकी और पैरासेलिंग जैसे पानी खेले के लिए भी ये बीच जाना जाता है। घोघ्ला बीच मछली पकड़ने वाले गांवों, चर्चों और किलों का विहगम दृश्य के लिए भी जाना जाता है। यहां आप ह-वाई मार्ग के ज़रिए पहुंच सकते हैं।

रुशिकोंडा बीच

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर से लगभग 15 से 20 किलो मीटर की दूरी पर है। ताड़ और नारियल के पेड़ों से घिरे इस बीच के किनारे घूमने का एक अलग ही मज़ा है।

विशाखापट्टनम में ऐसे कई पर्यटन स्थल है जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। इस बीच से कुछ ही दूरी पर संग्रहालय और विशाखापट्टनम चिड़ियाघर भी है जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। यहां ट्रेन, बस या हवाई मार्ग के जरिए पहुंच सकते हैं। विशाखापट्टनम कई प्रमुख बंदरगाहों के लिए भी जाना जाता है।

राधानगर बीच

राधानगर बीच भारत के अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में है। अगर आपको प्रकृतिक से प्रेम है तो ये जगह आपके लिए बेस्ट ट्रेवल डेस्टिनेशन हो सकता है। इस बीच के किनारे-किनारे आपको चारों तरफ हरियाली जी हरियाली दिखाई देगी। यह बीच सफेद रेत और नीले रंग के पानी के लिए मशहूर है। इसे एशिया का बेस्ट बीच भी माना है। इस बीच पर आप स्नोर्कलिंग, फसिगिं गेम, स्वीमिंग और स्कूबा डाइविंग आद का भी मज़ा उठा सकते हैं।

गोल्डन बीच

ओड़िसा अपने सुदंर समुद्र तटों के लिये पहले से ही जाना जाता है। यहां के प्रमुख समुद्री तटों से एक गोल्डन बीच को माना जाता है। इसे पूरी बीच के नाम से भी जाना जाता है। यह तट बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, जो एक लोकप्रिय और आकर्षण पर्यटक स्थलों से एक है। ओड़िसा में घूमने के लिए पर्यटन स्थलों की कमी नहीं है। यहां आप पूरी में श्री कृष्णा जी का मंदिर भी घूमने जा सकते हैं। वैसे ये बीच तैराकी और मछली पकडनें के लिए प्रमुख स्थान माना जाता है।

देश में कार्बन उत्सर्जन में आयी 15.4 प्रतिशत गिरावट

ललित मौर्य

लॉकडाउन की वजह से दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइट के स्तर में आई गिरावट ने पिछले सारे रिका-ॅर्ड तोड़े

2020 की पहली छमाही में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारी गिरावट देखने को मिली थी। पता चला है कि 2019 की तुलना में 2020 के पहले छह महीनों में कार्बन उत्सर्जन में 8.8 फीसदी की गिरावट आई थी। यदि जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से देखें तो यह बहुत अच्छी खबर है। शोध के अनुसार कोरोनावायरस और उससे जुड़े प्रतिबंधों के कारण ऐसा हुआ था। इन प्रतिबंधों ने अप्रैल 2020 तक करीब 390 करोड़ लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया था। जिससे ऊर्जा उपयोग, परिवहन, उद्योगों और व्यापर पर व्यापक असर पड़ा था।

यदि भारत की बात करें तो 2019 की तुलना में 2020 में जनवरी से जून के बीच कार्बन उत्सर्जन में 15.4 फीसदी की गिरावट देखी गई थी। जिसका मतलब है कि इस अवधि के दौरान कार्बन उत्सर्जन में 205.2 मीट्रिक टन की गिरावट आई थी। लॉक-डाउन की अवधि में कार्बन उत्सर्जन में सबसे बड़ी कमी अप्रैल में दर्ज की गई थी, जब उत्सर्जन में 44.2 फीसदी की गिरावट आ गई थी। इससे पहले फरवरी में इसमें 6.4 फीसदी की वृद्धि रिकॉर्ड की गई थी। बाद में मार्च के महीने में 16.9 फीसदी, अप्रैल मैं 44.2 फीसदी, मई में 27.6 फीसदी और जून में 15 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी।

वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में 1550.5 मीट्रिक टन की कमी

शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इस अवधि के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड में करीब 1550.5 मीट्रिक टन की कमी आई थी। यह कमी कितनी बड़ी है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते है कि इतिहास में पहली बार सीओ2 के उत्सर्जन में इतनी कमी देखी है।

इससे पहले द्वितीय विश्वयुद्ध, 1979 में तेल संकट और 2008 में आई आर्थिक मंदी के समय भी उत्सर्जन में इतनी ज्यादा कमी नहीं आई थी। हालांकि जुलाई के बाद चीन और यूरोप में प्रतिबंधों पर ढील दे दी गई थी। इसके बावजूद दुनिया के कई अन्य देशों में लॉकडाउन और अन्य प्रतिबन्ध जारी रखे गए थे। शोधकर्ताओं ने उत्सर्जन में आई इस गिरावट के लिए औद्योगिक गतिविधियों, परिवहन और ऊर्जा उपयोग में आई कमी को जिम्मेवार माना है। यह शोध अंतराष्ट्रीय जर्नल नेचर कम्युनिकेशन्स में प्रकाशित हुआ है। जिसे चीन, फ्रांस, जापान और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने किया है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए कार्बन उत्सर्जन के रियल टाइम डाटा का उपयोग किया है। जिसमें कोविड-19 महामारी के समय लगाए गए प्रतिबंधों के पहले और बाद में इकट्ठे किए गए आंकड़ों से प्राप्त दैनिक, साप्ताहिक और मौसमी रुझानों का विश्लेषण किया है। इससे पहले इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा जनवरी से अप्रैल 2020 की अवधि के दौरान 2019 की तुलना में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 5 फीसदी की कमी का अनुमान लगाया था।

यदि वैश्विक रूप से दैनिक कार्बन उत्सर्जन से जुड़े आंकड़ों के देखे तो अप्रैल 2020 में सबसे ज्यादा 16.9 फीसदी की गिरावट देखी गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार कार्बन उत्सर्जन में आई इस गिरावट के लिए मुख्य रूप से सड़क प-रिवहन जिम्मेदार था जिसकी वजह से उत्सर्जन में 613.3 मीट्रिक टन की गिरावट आई थी। जबकि ऊर्जा क्षेत्र से 341.4 मीट्रिक टन इंडस्ट्री से 263.5 मीट्रिक टन , विमान सेवाओं से 200.8 मीट्रिक टन अंतराष्ट्रीय शिपिंग से 89.1 मीट्रिक टन और आवासीय क्षेत्र से 42.5 मीट्रिक टन की गिरावट आई थी।

हमारे आज पर निर्भर है आने वाला कल

हालांकि कार्बन उत्सर्जन में आई यह गिरावट लम्बे समय तक कायम नहीं रहेगी पर इसने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि यदि सही दिशा में प्रयास किए जाएं तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं है। अनुमान है कि यदि 2020 से 2030 तक हर साल कार्बन उत्सर्जन में 7.6 फीसदी की कटौती की जाए तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

इस महामारी ने हमें एक बार फिर से यह सोचने का मौका दिया है कि हमारा आनेवाला कल कैसा होगा यह हमारे आज किए गए प्रयासों पर निर्भर होगा। आज भी रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, जीवाश्म ईंधन में कटौती, उद्योगों के लिए कड़े नियम और अपनी दिनचर्या में बदलाव करके इन लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। हमारे बच्चों का भविष्य हम पर निर्भर है और हमें तय करना है कि कल हम उन्हें कैसी धरती विरासत में देंगे।

पूर्वी यूपी में फाल्स स्मट महामारी से धान की फसल पर संकट

पूर्वी यूपी में धान की फसल पर फाल्स स्मट महामारी का असर हुआ है। इस महामारी के लिए जलवायु स्थितियां बेहद जिम्मेदार हैं। इससे धान की फसलें खराब हो रही हैं और किसान परेशान हैं। इसे कंडुआ रोग भी कहते हैं। इस बार इसका प्रकोप बहुत ही ज्यादा है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के करीब 23 जिले और सात मंडल में इसने 80 फीसदी तक धान की फसलों को प्रभावित किया है। इसका सबसे बड़ा कारण जलवायु स्थितियां हैं। बारिश और काफी नमी होने की वजह से फसलों में यह रोग फैला है। पॉयनियर, दामिनी जैसी अन्य कई वेराइटी में किसान इस रोग के लगने की शिकायत कर रहे हैं। यदि यह एक से दो फीसदी तक होता तो शायद दवाओं से इसकी रोकथाम होती लेकिन यह 50 फीसदी से ज्यादा फसलों को प्रभावित कर चुका है। हवा और नमी के कारण यह काफी तेजी से फैला है। फिलहाल किसान प्रोपिकोनाजोल-25, कार्बडाजिम 50 डब्ल्यू पी का 200 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि अब बहुत देर हो चुकी है और कितनी दवाई डाले। कटाई का वक्त है, ऐसे में धान की बालियों में पीले फंगस वाले गोले काफी नुकसान कर देंगे।

इस बार देश में धान की बंपर रोपनी हुई थी। लॉकडाउन में गांव को लौटे प्रवासियों नें धान की बंपर रोपनी की है।

गर्मियों में प्रदूषण स्तर ज्यादा

वायु प्रदूषण के बढ़ने और घटने में मौसम का बड़ा किरदार है। अभी सर्दी के दौरान अनुभव किए जाने वाले वायु प्रदूषण पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जबकि गर्मी के वायु प्रदूषण की प्रकृति अभी थोड़ी अनसुलझी है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा जारी ''क्लीन एयर ब्ल्यू स्काइज, एयर पाल्यूशन डयूरिंग ए समर ऑफ लॉकडाउन'' रिपोर्ट में कहा गया है कि गर्मी के मौसम में सामान्य तौर पर तापामान ज्यादा होता है और हवाओं की रफ्तार तेज होती है साथ ही रुक-रुक कर वर्षा भी होती है। जबकि सर्दियों में इसके एकदम विपरीत ठंडी और ठहरी हुई मंद गति वाली हवा प्रदूषकों को कैद कर लेती हैं। इसलिए, वायु गुणवत्ता पर मौसम के प्रभाव अलग-अलग होते हैं। वहीं, गर्मियों के मौसम की अपेक्षा सर्दियों के मौसम की तुलना में धूल की अधिकता हो जाती है, साथ ही वायुमंडल में गैसों से बनने वाले द्वितीयक कणों की सघनता बढ़ जाती है।

भौतिकी का नोबेल ब्लैक होल से जुड़ी खोजों को मिला

एजेंसियां

इस साल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रोजर पैनरस, राइनहार्ड गैन्जेल और आंद्रे गेज को दिया जाएगा। तीनों वैज्ञानिकों की खोज अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल से जुड़ी है।

यूके में पैदा हुए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले रोजर पैनरस ने पता लगाया है कि ब्लैक होल के निर्माण को सापेक्षता के सिद्धांत पर समझा जा सकता है। यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। दूसरी तरफ हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली ऑब्जेक्ट यानी ब्लैकहोल की खोज के लिए राइनहार्ड गेंजल और आंद्रेया गेज को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राइनहार्ड गेंजल जर्मनी में पैदा हुए और माक्स प्लांक इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं। आंद्रेया गेज अमेरिका से हैं और युनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजेलेस में प्रोफेसर हैं।

अतिसूक्ष्म कणों से लेकर ब्रह्मांड के विशाल रहस्यों को सुलझाने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाता

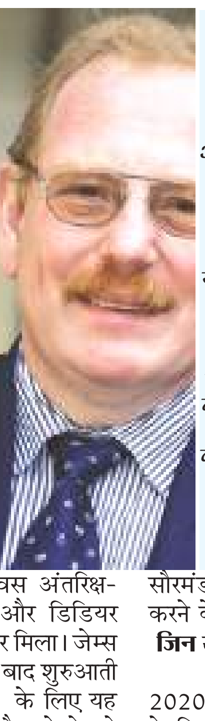

रहा है। स्टॉकहोम की कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने आज इसका एलान किया है। एक ही क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों के बीच इस पुरस्कार का बांटा जाना अब आम बात हो गई है। पिछले साल कनाडा में जन्मे ब्रह्मांडविज्ञानी जेम्स पीबल्स और स्विस अंतरिक्ष-विज्ञानी मीषेल मेयर और डिडियर क्वेलोज को यह पुरस्कार मिला। जेम्स पीबल्स को बिग बैंग के बाद शुरुआती समय पर काम करने के लिए यह पुरस्कार मिला तो मेयर और क्वेलोज ो सौरमंडल के बाहर ग्रहों की खोज करने के लिए।

दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। इस बार पुरस्कार विजेता को करीब 11 लाख अमेरिकी डॉलर की रकम मिलेगी। महंगाई को देखते हुए हाल ही में पुरस्कार की राशि बढ़ाई गई है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी और इसी दिन यह पुरस्कार दिए जाते हैं। कोरोना की महामारी के कारण इस साल विज्ञान, साहित्य और शांति पुरस्कारों के विजेताओं को उनके देश में ही पुरस्कार दिया जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होने वाला समारोह भी संक्षिप्त रहेगा। शांति पुरस्कार विजेता को पुरस्कार या तो ओस्लो में दिया जाएगा या फिर ऑनलाइन समारोह के जरिए।

जिन खोजों के लिए मिला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार

2020 में ब्लैक होल से जुड़ी खोज के लिए ब्रिटेन के रोजर पैन्सर, जर्मनी राइनहार्ड गेंजल और अमेरिका की आंद्रेया गेज को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा।

1901 से लेकर 2019 के बीच भौतिकी के लिए कुल 113 नोबेल पुरस्कार दिए गए। 1916, 1931, 1934, 1941 और 1942 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। पुरस्कार नहीं देने के बारे में नोबेल फाउंडेशन के संविधान का कहना है कि जब कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलेगा तब यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में पुरस्कार की राशि अगले साल तक के लिए सुरक्षित रख दी जाएगी। अगर उसके अगले साल भी कोई नहीं मिला तो यह धन फाउंडेशन के प्रतिबंधित कोष में डाल दी जाएगी। विश्वयुद्धों के दौर में कम नोबेल पुरस्कार दिए गए।

भौतिकी में 47 बार यह पुरस्कार एक विजेता को मिला जबकि 32 बार इसके दो विजेता रहे और 34 बार तीन वैज्ञानिकों ने पुरस्कार साझा किया। जॉन बार्डीन नाम के वैज्ञानिक को दो बार नोबेल पुरस्कार मिला है। इस तरह कुल 212 लोगों ने 213 पुरस्कार हासिल किए हैं। अब तक केवल तीन महिलाएं ही यह पुरस्कार जीत सकीं हैं। इनमें मैरी क्यूरी को 1903 में, मारिया गोएपर्ट मायर को 1963 में और 2018 में डोना स्ट्रिकलैंड को यह पुरस्कार दिया गया। दो बार नोबेल पुरस्कार जीतने वालों में मैरी क्यूरी भी हैं लेकिन उन्हें दूसरा पुरस्कार रसायन के लिए मिला। मैरी क्यूरी का उदाहरण अनोखा है क्योंकि उनके पति और बेटी-दामाद को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। भौतिक के नोबेल के सबसे युवा विजेता लॉरेंस ब्रैग हैं जिन्हें 25 साल की उम्र में उनके पिता के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसी तरह सबसे अधिक उम्र के नोबेल विजेता के रूप में आर्थर आश्किन का नाम दर्ज है जिन्हें 2018 में जब पुरस्कार मिला तब उनकी उम्र 98 साल थी। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी हैं। उन्हें 1921 में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला।

केएसपीसीबी ने एनजीटी के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) ने पर्यावरण प्रयोगशालाओं के लिए मान्यता पर एनजीटी के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

कर्नाटक में केवल तीन निजी पर्यावरण प्रयोगशालाएं हैं, जिन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मान्यता प्राप्त की है। राज्य में 65,000 से अधिक उद्योग चल रहे हैं और उन्हें जल और वायु अधिनियम के अनुसार पानी, हवा, शोर और मिट्टी के नमूनों की निगरानी की आवश्यकता होती है। इन सीमित मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से नमूनों का विश्लेषण कर शीघ्र परिणाम प्राप्त करना संभव नहीं है।

इसके अलावा, उद्योग से दूर स्थित प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए नमूनों को ले जाना व्यावहारिक नहीं है। इस पृष्ठभूमि में केएसपीसीबी के अध्यक्ष ने नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मान्यता प्राप्त करने के लिए 6 महीने का समय बढ़ाया था। इससे उद्योगों को पर्यावरण कानूनों का पालन करने में मदद मिलेगी, जिनका पालन करना अनिवार्य है, जिनमें पानी, हवा, ध्वनि और मिट्टी के नमूने का विश्लेषण करना शामिल है।

रिपोर्ट में एनजीटी से अनुरोध किया गया है कि वह पर्यावरण और जनता के हित में उचित समय में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मान्यता प्राप्त करने के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को अनुमति दे। एनएबीएल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है। यह परीक्षण और जांच करने वाली प्रयोगशालाओं के लिए गुणवत्ता और तकनीकी क्षमता के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। एनएबीएल प्रयोगशालाओं को प्रयोगशाला मान्यता सेवाएं प्रदान करता है जो एनएबीएल मानदंड के अनुसार परीक्षण / जांच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों और दिशानिर्देशों पर आधारित है।

पंचकूला में हो रहे अवैध खनन की जांच कार्रवाई का आदेश

एनजीटी ने 14 अक्टूबर 2020 को अंबाला के कमिश्नर के लिए एक निर्देश जारी किया है, जिसमें उन्हें पंचकूला में हो रहे अवैध खनन की जांच और उसपर उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है। अवैध खनन का यह मामला हरियाणा में पंचकूला के श्यामाडू गांव का है, जहां कृषि भूमि पर अवैध खनन किया जा रहा था। इस मामले में आवेदक मनीष कुमार ने कोर्ट को जानकारी दी है कि यहां पर नियमों का उल्लंघन कर 100 फीट तक की गहराई पर खनन किया जा रहा था। जिससे फसलों और कृषि क्षेत्रों को नुकसान होने की संभावना है।

झारखंड में तेलहनी फसलों की खेती की संभावना

झारखण्ड में तेलहनी फसलों की खेती की बहुत ही अच्छी संभावना है इस विषय पर ग्रीन रिवोल्ट ने बीएयू के तेलहन फसल विशेषज्ञ डॉ. सोहन राम से खास बातचीत की है। उन्होंने विस्तार से इसके बारे में हमें बताया।

भारत में तिलहन उत्पादन का अनुमान

अमेरिकी कृषि विभाग की ग्लोबल एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक अनुकूल मौसम और बढ़ते रोपण क्षेत्र की वजह से भारत का तिलहन उत्पादन वर्ष 2020-21 में बढ़ने का अनुमान जताया है। तिलहन उत्पादन के मामले में भारतीय बाजार में सोयाबीन, रेपसीड,सरसों,मूंगफली, सूरजमुखी फसल प्रमुख हैं और 2 प्रतिशत की दर से 38.4 मिलियन टन तक उत्पादन बढ़ने का अनुमान जताया गया है।

भारत में खाद्य तेल का आयात अनुमान

देश में तिलहन उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, यूएसडीए ने पिछले कुछ वर्षों में आयात की प्रवृत्ति को ट्रैक कर पिछले साल की समान अवधि की तुलना में भारत से तेल के आयात में तेजी के बारे में बताया है। यूएसडीए का अनुमान है कि भारत 2020-21 के बाजार वर्ष में 2.5 मिलियन टन तेल भोजन का निर्यात करेगा। इस मजबूत खपत मांग से भारत के तेल खाद्यान व्यापार अधिशेष पर दबाव पड़ने की उम्मीद है।

झारखण्ड प्रदेश में तिलहन फसलों की स्थिति

वर्षा आधारित कृषि झारखंड राज्य की प्रमुख विशेषता है। प्रदेश के शुद्ध खेती वाले क्षेत्रों में 10-12 प्रतिशत मात्र सिंचाई की सुविधा है। यह फसल की तीव्रता में कमी (100 प्रतिशत से ऊपर) की मुख्य वजह है। खाद्यान, दलहन और तेलहन फसलों की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। देश के कृषि विकसित राज्यों की तुलना में भी फसलों की उत्पादन एवं उत्पादकता बहुत कम है। राज्य में चावल, गेहूं और अन्य अनाज के मामले क्रमशः 49%, 91% और 47% की कमी बताई जाती है। जबकि दलहन और तेलहन के मामले में यह 48 और 71 प्रतिशत तक है। सूखे के वर्षों के दौरान समस्याएं बढ़ जाती हैं।

झारखंड में कृषि परिदृश्य के पिछड़े स्वरूप को देखते हुए, केंद्र एवं राज्य सरकार तथा अन्य संगठनों द्वारा राज्य में फसलों और संबद्ध गतिविधियों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अनेकों योजनाएं चल रही हैं। राज्य गठन के बाद तेलहनी फसलों के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 1999-2000 में तेलहनी फसलों का रकबा महज 59 हजार हेक्टेयर था, जो वर्ष 2006- 07 में बढ़कर करीब 157 हजार हेक्टेयर हो गया। वर्ष 2009-10 में तेलहनी फसलों के क्षेत्र में थोड़ा गिरावट पाया गया। बाद के वर्षों में बढ़ता रुझान दिखा। जो वर्ष 2013 में करीब 260 हजार हेक्टेयर तक पहुंच गया। वर्ष 2014 से उत्पादकता में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई है। जो बाद के वर्षों में कुछ फसलों को छोड़कर ज्यादातर तेलहनी फसलों की उत्पादकता मामले में एक निरंतरता के रूप में चिह्नित किया गया है। हालांकि वर्ष 2013-14 के दौरान औसत उत्पादकता 790 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देखी गई थी।

तिलहन फसल के क्षेत्र में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का योगदान

झारखंड प्रदेश की कृषि पारिस्थिकी के अनुकूल तेलहनी फसलों के उन्नत किस्मों के विकास में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) का काफी सराहनीय योगदान रहा है। बीएयू के आनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग द्वारा विकसित मूंगफली किस्म बिरसा बोल्ड ने देश भर में पहचान स्थापित की है। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मूंगफली की अन्य दो किस्म बिरसा मूंगफली -3 व बिरसा मूंगफली -4 तथा सोयाबीन फसल किस्म बिरसा सोयाबीन -1 तथा बिरसा सफ़ेद सोयाबीन -2 किसानों के बीच लोकप्रिय है।

विभाग के मुख्य वैज्ञानिक एवं तेलहनी फसल विशेषज्ञ डॉ सोहन राम ने वर्ष 1994 से वर्ष 2016 तक की अवधि में सरगुजा (नाईजर), सरसों (मस्टर्ड) एवं तीसी (तीनसीड) के कुल 7 उन्नत किस्मों का विकास किया है। इन्हें झारखण्ड राज्य में तेलहन फसल किस्मों का जनक कहा जा सकता है। इन्होंने सरगुजा की बिरसा नाईजर - 1 (1994), बिरसा नाईजर - 2 (2003) व बिरसा नाईजर - 3 (2008), सरसों की शिवानी (2003) व पूजा -1 (2009) तथा तीसी (अलसी) की दिव्या (2015) एवं प्रियम (2016) को विकसित किया है। इन सभी किस्मों का प्रदर्शन झारखण्ड एवं बिहार राज्य में काफी बेहतर देखा गया है। ये सभी किस्में प्रदेश के किसानों के बीच लोकप्रिय है।

वर्ष 2019-20 में तिलहन फसल के रकबा व उत्पादन में बढ़ोतरी

हाल के दिनों में बिहार एवं झारखण्ड के 65 कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) के वैज्ञानिकों की समीक्षा बैठक में तिलहनी फसल के रकबे में करीब 18 प्रतिशत तथा उत्पादन में करीब 20 - 25 प्रतिशत वृद्धि की बात सामने आई। यह आकलन केवीके द्वारा कराये गये तिलहन फसल के संकुल स्तरीय अग्रपंक्ति प्रत्यक्षण के प्रतिवेदन से ज्ञात हुआ। बैठक में झारखंड में दलहनी फसलों के उत्पादन मामले में बहुत हद तक आत्मनिर्भरता को देखते हुए तेलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए विशेष कार्यनीति बनाने पर बल दिया गया। झारखण्ड स्थित सभी 24 जिलों में स्थित केवीके ने प्रदेश के किसान द्वारा सरसों की अंतरफसली खेती की जगह खेतों में शुद्ध सरसों की खेती अपनाने के बारे में बताया। राज्य में तेलहनी फसलों में सरगुजा, तीसी एवं तिल की खेती में गुणात्मक सुधार देखने को मिला।

तेलहन फसलों के किस्मों के विकास में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) का अग्रणी स्थान रहा है। विश्वविद्यालय के आनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग के मुख्य वैज्ञानिक (तेलहन) डॉ सोहन राम ने वर्ष 1994 से 2016 तक सरगुजा (नाईजर) की चार, सरसों (मस्टर्ड) की एक तथा तीसी (अलसी, लीनसीड) के दो किस्मों का विकास किया है। झारखण्ड एवं बिहार राज्य के केवीके द्वारा कराये गये संकुल स्तरीय अग्रपंक्ति प्रत्यक्षण में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सरगुजा की किस्में बिरसा नाईजर -1, बिरसा नाईजर -2 और बिरसा नाईजर -3 का प्रदर्शन काफी बेहतर पाया गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित इन किस्मों को राष्ट्रीय बीज प्रमाणन एजेंसी द्वारा अनुशंषित तथा रिलीज किया गया है। ये सभी किस्में झारखण्ड एवं इसके समान अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए काफी लाभकारी पाये गये है।

डॉ सोहन राम बताते है कि इन किस्मों के स्टेट सीड चैन में बढ़ावा तथा संरक्षण देने की जरूरत है। जिसके अभाव में झारखंड प्रदेश को इन विकसित किस्मों का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

झारखण्ड राज्य गठन के बाद वर्षवार तिलहन का कुल आच्छादन एवं उत्पादन

वर्ष	आच्छादन (हजार हे. में)	उत्पादन (हजार मि. टन में)
2001-02	75	50
2002-03	94	60
2003-04	101	40
2004-05	94	53
2005-06	85	47
2006-07	145	72
2007-08	124	69
2008-09	131	73
2009-10	141	67
2010-11	186	89
2011-12	229	156
2012-13	251	197
2013-14	276	183
2014-15	278	192
2015-16	283	189
2016-17	361	264
2017-18	417	297
2018-19	334	225

तेलहनी फसलों में प्रदेश में खरीफ मौसम में मूंगफली, सोयाबीन,सरगुजा, तिल तथा रबी मौसम में कुसुम, तीसी, तोरी - राई एवं सूर्यमुखी की खेती की जाती है।

बीएयू ने सरगुजा (नाईजर) की किस्मों में बिरसा नाईजर -1, बिरसा नाईजर -2, बिरसा नाईजर -3 तथा पूजा -1 को विकसित किया है. सरसों (मस्टर्ड) की एक किस्म शिवानी तथा तीसी (अलसी) के दो किस्मों दिव्या एवं प्रियम को विकसित किया है. इन किस्मों को तकनीकी प्रदर्शन के माध्यम से केवीके एवं क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों द्वारा प्रसार कार्य किये जा रहे है. डॉ सोहन राम का कहना है कि तेलहनी फसल में अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य द्वारा मिशन मोड में अभियान चलाने की जरूरत है।

केंद्र एवं राज्य सरकार तेलहनी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, तीसी व सूर्यमुखी की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। चालू रबी मौसम में प्रदेश में स्थित 10 कृषि विज्ञान केन्द्रों में आयल सीड हब कार्यक्रम चालू होने जा रही है। इसमें राज्य के किसानों को परम्परागत बीज की जगह इन फसलों के उन्नत व संकर प्रभेद के बीज का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा .साथ ही रबी में परती व असिंचित भूमि में कम उत्पादक अनाज फसलों के स्थान पर इन तेलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से तेलहनी फसलों के क्षेत्र विस्तार को बढ़ावा मिलेगा और भूमि की उर्वरता भी बरकरार रहेगी. तेलहन उत्पादन के क्षेत्र में राज्य आत्मनिर्भरता की ओर अग्रणी होगा. तेलहन फसल की खेती से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है. साथ ही ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर में भी वृद्धि होगी।

झारखण्ड राज्य में तिलहन फसलों का आच्छादन एवं उत्पादन

फसल	आच्छादन	उत्पादन	उत्पादकता
खरीफ तिलहन फसल	(हजार हे. में	(हजार मि. टन में)	
तिल	14.634	5.127	350.362
सोयाबीन	6.009	4.555	746.857
मूंगफली	30.072	31.045	800.00
अंडी	0.041	0.026	631.512
सूर्यमुखी (खरीफ)	0.358	0.198	552.123
सरगुजा	4.743	2.600	548.114
रबी तिलहन सरसों	236.853	164.645	695.134
तीसी	39.738	19.52	490.859
कुसुम	0.775	0.452	583.342
सूर्यमुखी (रबी)	0.705	0.324	458.865

प्रदेश में कुसुम की खेती के लिए ए. - 300 तथा अक्षागिरी -59-2-1 किस्में अनुशंसित हैं. अगात धान काटने के तुरंत बाद दो - तीन जुताई के बाद पाटा चलाकर खेत की तैयारी करनी चाहिए. इसकी बुआई मध्य अक्टूबर से नवम्बर के प्रथम सप्ताह तक की जा सकती है. अधिक ठण्ड पड़ने से बीज अंकुरण पर बुरा असर पड़ता है. एक हेक्टेयर के लिए 15-20 कि. ग्रा. बीज की आवश्यकता होती है. बुआई में कतार की दूरी 30-45 से. मी. रखनी चाहिए. बुआई के समय 25 कि. ग्रा. यूरिया, 45 कि. ग्रा. डी.ए.पी. तथा 34 कि. ग्रा. एम. ओ. पी. का प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करना चाहिए. बुआई के एक माह के अंदर निकाई - गुडाई अवश्य कर लेनी चाहिए. कुसुम में रोग एवं कीट का प्रकोप कम होता है।

तोरी - राई एवं पीला सरसों

प्रदेश में तोरी की खेती के लिए पी. टी. 203 व पंचाली, राई की खेती के लिए शिवानी, पूसा बोल्ड, पूसा मस्टर्ड - 25 व एन.आर.सी.एच.बी. - 101 तथा पीला सरसों के लिए एन.आर.सी.वाई. एस. - 05-02 किस्मों की अनुशंसा की जाती हैं. इसकी उपज क्षमता 4-10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा करीब 42 प्रतिशत तेल की मात्रा पाई जाती है. एक हेक्टेयर में बुआई के लिए 5 कि. ग्रा. बीज की आवश्यकता होती है. बुआई में कतारों की दूरी 30 से. मी. तथा पौधों की दूरी 10 से. मी. रखनी चाहिए. तोरी में 50 :25 :25 :20 कि. ग्रा. नेत्रजन, स्फूर, पोटाश एवं सल्फर तथा राई में 80 :60 :40 :20 कि. ग्रा. नेत्रजन, स्फूर, पोटाश एवं सल्फर उर्वरक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करना चाहिए.।

सूर्यमुखी

सूर्यमुखी की खेती के लिए डी.आर.एस.एफ. - 108 (ओपी) तथा के.बी. एस.एच. (संकर) किस्में अनूशंषित हैं. अगात धान काटने के तुरंत बाद दो - तीन जुताई के बाद पाटा चलाकर खेत की तैयारी करनी चाहिए. रबी में बुआई के पूर्व खेतों में पर्याप्त नमी का होना जरूरी है. इसकी बुआई अक्टूबर से नवम्बर के प्रथम सप्ताह तक की जा सकती है. एक हेक्टेयर के लिए 8-10 कि. ग्रा. बीज की आवश्यकता होती है. बुआई में कतारों की दूरी 60 से. मी. तथा पौधों की दूरी 30 से. मी. रखनी चाहिए. बुआई के समय 40 कि. ग्रा. नेत्रजन, 50 कि. ग्रा. स्फूर, 50 कि. ग्रा. पोटाश एवं 25 कि. ग्रा. सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करना चाहिए. बुआई के 20-25 दिनों बाद तथा 35-40 दिनों के बाद निकाई - गुडाई अवश्य कर लेनी चाहिए. इसकी खेती में बुआई के 20-25 दिनों बाद 3 सिंचाई की जरूरत होती है।

तीसी (अलसी)

प्रदेश में तीसी की खेती के लिए दिव्या (सिंचित), प्रियम (असिंचित) तथा सुरभि किस्में अनुशंषित हैं. इसकी उपज क्षमता 9-12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा करीब 43 प्रतिशत तेल की मात्रा पाई जाती है. अगात धान काटने के तुरंत बाद दो - तीन जुताई के बाद पाटा चलाकर खेत की तैयारी करनी चाहिए. इसकी मध्य अक्टूबर से मध्य नवम्बर तक की जा सकती है. एक हेक्टेयर के लिए 22 - 25 कि. ग्रा. बीज की आवश्यकता होती है. बुआई में कतारों की दूरी 30 से. मी. रखनी चाहिए. बुआई के समय 30 कि. ग्रा. नेत्रजन, 20 कि. ग्रा. स्फूर, 20 कि. ग्रा. पोटाश एवं 20 कि. ग्रा. सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करना चाहिए. बुआई के एक माह के अंदर निकाई - गुडाई अवश्य कर लेनी चाहिए. रोगग्रस्त भूमि में तीसी की खेती नहीं करनी चाहिए. किरण एवं आर -552 रोग रोधी किस्मों का व्यवहार की जा सकती है।

रांची रेल मंडल का व्यवसायीयों ,प्रतिनिधियों से बेबिनार में चर्चा

रांची :14अक्टूबर को अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) एम एम पंडित की परिस्थति में रांची रेल मंडल पर कार्यरत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों से, व्यापारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था की लोडिंग एवं अनलोडिंग करने वाले सभी व्यवसायियों की सुविधा के लिए सभी प्रकार से मदद की जाए तथा रेल प्रशासन की ओर से अनुरोध किया गया कि रेलवे के प्रति उनकी जो भी बकाया है उन्हें जल्द से जल्द भुगतान कर रेलवे की सहायता करें। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन)एम एम पंडित ने कहा कि आपके दिए गए सुझाव पर विचार कर उचित कार्रवाई की जाएगी

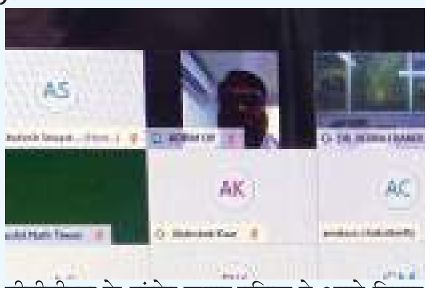

इस वेबीनार बैठक में हिंडालको मुरी के यशपाल नेगी, सीसीएल के गणेश अग्रवाल, हिंडालको लोहरदगा के अभिषेक कुमार, एफसीआई रांची के गौरव मेहता, गोदावरी कमोडिटीज के संजीव कुमार, बीसीसीएल के संतोष कुमार मलिक ने अपने विचार रखे एवं सुझाव दिए साथ ही इस बैठक में वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय) अमित कंचन वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक श्री नीरज कुमार, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवनीश, मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉक्टर देवराज बनर्जी, सहायक वित्त प्रबंधक टी आर मीणा, एवं मंडल के सभी पार्सल सुपरवाइजर तथा वाणिज्य निरीक्षक इस वेबीनार में भाग लिए।

सीपीसीबी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जरूरी और उचित कदम उठाने के लिए कहा

कूड़े और प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जरुरी और उचित कदम उठाने के लिए कहा है। साथ ही उसके लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने का आदेश दिया है। जानकारी मिली है कि 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्लास्टिक की करीब 615 अवैध यूनिट चल रही हैं। इस कचरे से निपटने के लिए 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष पर्यावरणीय दस्तों की स्थापना की गई है। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक स्थानों, नालियों, नदियों और समुद्र में प्लास्टिक कचरे की डंपिंग न की जा सके। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके की प्लास्टिक कचरे को खुले में न जलाया जाए।

सीसीएल में 'विचार-मंथन सत्र' का सफल आयोजन

रांची :17 अक्टूबर को सीसीएल मुख्यालय, रांची में सीसीएल के सीएमडी पी.एम. प्रसाद की अध्यक्षता में 'विचार-मंथन सत्र (Brain-Storming Session)' का सफल आयोजन किया गया। विचार-मंथन सत्र में सीसीएल के निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त) एन.के. अग्रवाल सहित सीसीएल मुख्यालय के विभिन्न विभागों के महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, क्षेत्रिय महाप्रबंधक एवं उनकी टीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला का उत्पादन पूर्णतः सुरक्षित तरीके से सुनिश्चित करना है।

इस अवसर पर सीएमडी पी.एम. प्रसाद ने सेफ्टी कमिटी तथा वर्कमेन इंस्पेक्टर की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की एवं आवश्यक निर्देश दिये। साथ ही साथ उन्होंने सभी को प्रेरित करते हुये खान में सभी वैधानिक पदों पर कार्यरत अधिकारी एवं सुपरवाइज़र को अपनी कार्य संबन्धित डायरी अपडेट रखने का निर्देश भी दिया। विचार-मंथन सत्र में महाप्रबंधक (सेफ्टी), एस.वी. मराठे ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति कोड-2020 (OSHWC-2020)'' एवं अन्य सुरक्षा पहलुओं पर पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण दिया। कार्यक्रम में सीसीएल सेफ्टी बोर्ड सदस्यों ने खान सुरक्षा संबन्धित अपने-अपने विचार एवं सुझाव दिये। साथ ही सभी उपस्थित सदस्यों से सर्वश्रेष्ठ प्रणालीको अपनाने के विषय पर विचार लिए गए। यह पूरा कार्यक्रम वीडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्यालय की सेफ्टी विभाग के सदस्यों की भूमिका रही।

कोरोना की मार सबसे ज्यादा गांव की महिलाओं पर

एजेंसियां

अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पर यून की ओर से कहा गया कि इस वक्त देश की सरकारों को सबसे ज्यादा ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा में निवेश करने की जरूरत है। अगर हम इस महामारी के दौरान ग्रामीण महिलाओं को प्राथमिकता नहीं देते हैं तो हमारी खाद्य आपूर्ति पर निश्चित खतरा है। इस खतरे को भांपते हुए यून के इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (आईएफएडी) के अध्यक्ष गिलबर्ट एफ हौंगबो ने बेहद ताकत के साथ सभी सरकारों से यह अपील की है कि वे ग्रामीण महिलाओं में अपने निवेश को अधिक से अधिक बढ़ाएं।

हौंगबो ने 15 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के मौके पर कहा "हमारे खाने के लिए अनाज उगाने वाली और अर्थव्यवस्था को बनाए रखने वाली ग्रामीण महिलाएं महामारी के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। यह स्वीकार करने योग्य नहीं है।" उन्होंने कहा कि वैश्विक लचीलापन इस बात पर निर्भर करता है कि सरकारें ग्रामीण महिलाओं की रक्षा के लिए अपने निवेश को कितना बढ़ाती हैं और उनकी असमान सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर कितना अधिक ध्यान देती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली करीब 1.7 अरब महिलाएं और लड़कियां है जो पूरी मानवता का एक-पांचवा हिस्सा है। विकासशील देशों में कृषि कार्य बल का 43 फीसदी हिस्सा ग्रामीण महिलाएं ही हैं और दुनिया के अधिकांश खाद्य उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बावजूद उनके पास तकनीकी, बाजार और वित्तीय संपत्तियों के अलावा कृषि संसाधनों को हासिल करने का अवसर पुरुषों के मुकाबले कम हैं। और यही बात उन्हें इस महामारी के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली है। गतिविधि करने के लिए लगाई गई पाबंदियां और खींची गई सीमा रेखाएं ग्रामीण उत्पादकों को उनकी उपज और उत्पाद को बिक्री में बड़ी बाधा बन रही हैं। ग्रामीण महिलाएं जो कि बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के अनौपचारिक तौर पर रोजगार हासिल करती हैं, इस महामारी के दौरान पुरुषों के मुकाबले सबसे ज्यादा ग्रामीण महिलाएं बेरोजगारी का सामना कर रही हैं। वहीं, अवैतनिक घरेलू काम का बोझ भी उन पर बढ़ रहा है जिसमें वे अपने परिवार के बीमार सदस्यों और स्कूल न जा सकने वाले बच्चों की देखभाल कर रही हैं।

हौंगबो ने कहा "ग्रामीण महिलाएं, जिन लोगों पर अगली पीढ़ी को खिलाने और पालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें इस संकट के माध्यम से उपेक्षित किया गया है।" "यह उनके परिवार, समुदायों और उनके देशों की अर्थव्यवस्थाओं में उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को बढ़ाने का समय है। इस अभूतपूर्व समय में उनके समर्थन और सुरक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए।"

बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन द्वारा 25 वर्षों में बहुत प्रगति की गई है जिसने महिलाओं के सशक्तिकरण को संबोधित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है। ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक समानता प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। वहीं, यह ध्यान रखना चाहिए कि 25-34 वर्ष की आयु की महिलाएं अभी भी पुरुषों की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक गरीबी में रहने की संभावना रखती हैं।

लंदन से रोम की दूरी जितनी बनेगी साइकिल लेन

कोविड-19 ने दुनिया को वायु प्रदूषण कम करने के लिए एकदम से जागरूक बना दिया है और लोगों का कहना है कि वे 'नए सामान्य' में वायु प्रदूषण के पूर्व-महामारी के स्तर को नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ तक कि यूरोप जैसे विकसित देशों में रहने वाले अपने शहरों में कारों की जगह साइकिल चलने लगे हैं और कारों का विरोध करते नजर आ रहे हैं।

लोगों की सोच में आये इस बदलाव से दुनिया में अधिकांश जगह वायु प्रदूषण की समस्या को राहत मिलती नजर आ रही है। लोग साइकिल से चलने लगे हैं और दुनिया भर के शहर इस शिफ्ट का समर्थन करने के लिए तेजी से आगे बढ़े हैं। जब से महामारी शुरू हुई 2,000 किमी से अधिक नई साइकिल लेनों की घोषणा की गई, यह फासला लंदन से रोम की दूरी के बराबर है। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के जवाब में दुनिया भर के शहर लॉकडाउन में चले गए, दुनिया भर के लोगों ने कम औद्योगिक गतिविधि और परिवहन संरचनों से हवा की गुणवत्ता में सुधार के परिणामस्वरूप स्पष्ट, नीले आसमान को देखा।

यूरोप में लगभग दो-तिहाई लोगों ने कहा कि वे वायु प्रदूषण के पूर्व-महामारी के स्तर पर वापस नहीं लौटना चाहते हैं, और 68% लोगों का कहना है कि वे वायु प्रदूषण को कम करने वाली नीतियां - जिनमें शहर के केंद्रों में कारों पर प्रतिबंध लगाना शामिल हो - बरकरार रखना - चाहते हैं। लोग साइकिल चलाना और पैदल चलना बड़ी संख्या में पसंद कर रहे हैं - कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप कई देशों में साइकिल और अन्य सक्रिय यात्रा मोड में 'विस्फोट' हुआ। मिसाल के तौर पर यूनाइटेड किंगडम में, 5% उपभोक्ताओं ने लॉकडाउन के दौरान एक बाइक (साइकिल) खरीदी। दुनिया भर में, सार्वजनिक स्थान के उपयोग की पुनः कल्पना करने के लिए शहर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, साइकिल चलाने और चलने के लिए अधिक स्थान बना रहे हैं, ताकि पड़ोस को रहने लायक बना सकें और सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद कर सकें।

फोटो न्यूज

बर्बाद कर दिया गया सालो भर जल देने वाला रातूरोड रांची का यह कुंआ

रांची : भारतीय संस्कारों में कुंए को देवतूल्य स्थान दिया गया है। अनुपयोगी कुंए को भी जल्दी से भर कर खत्म करना पाप समझा गया है। चित्र में दिखाया गया सरकारी कुंआ रांची के रातू रोड इलाके के अल्कापुरी का है। कभी भयंकर गर्मियों में भी इस कुंए का जल सूखता नहीं था। और आस पास के लोगों के अलावा छोटे होटलों एवं दूकानदारों को भी जल उपलब्ध कराता था।

यह कुंआ एक बहुत ही घनी आबादी के बीच स्थित है जिसके चारो ओर बहुत सारे मकान हैं और बहुत ही संकरी गलियां हैं जिसमें बड़े वाहन भी नहीं जा सकते। यहां डीप बोरिंग के वाहनों का घुसना संभव नही है। कभी यहां आस पास के लोग भी नहाते थे, और पूरे मुहल्ले के जल की जरूररत को यह कुंआ पूरा करता था, पर यहां के बाशिंदों ने ही इसे बर्बाद कर दिया। कुछ लोगों ने इसकी जमीन कब्जाने के मकसद से पहले इसमें कचड़ा डाल कर अनुपयोगी बना दिया, अब यह पूरी तरह से कचड़ा डंप करने का गड्ढा मात्र रह गया है।

शरीर का डीटॉक्स क्या है ?और इसे क्यों करना चाहिए

ऋतु सिंह, योग प्रशिक्षक

शरीर का डीटॉक्स भाग 2

आज हम बात करेगें शरीर के डीटॉक्स के कुछ तरीकों के बारे में । पहले देखते हैं अगर शरीर का डीटॉक्स करना है तो किन- किन आन्तरिक अंगों को साफ करना होगा जैसे हमारे फेफड़ों, गुर्दो (किडनी) और जिगर (लीवर) का डीटॉक्स करना जरूरी है। हमारी त्वचा भी काफी अवांछित तत्वों को रोम छिद्रों के द्वारा बाहर निकल देती है। शरीर को डीटॉक्स करने के कई तरीके है । कुछ के बारे में आज हम बात करेगें।

- एनीमा
- कोलोन थेरेपी
- उपवास
- पंचकर्म
- प्राणायाम

●एनीमा - इस विधि में इंजेक्शन के द्वारा कोई तरल पदार्थ मल के रास्ते छोड़ा जाता है। इससे पूरे मलाशय और आंतों की अच्छे से मल के द्वारा सफाई हो जाती है।

●कोलोन थेरेपी- बृहदांत्र हाइड्रोथेरेपी या कोलोन थेरेपी। कोलोन उत्सर्जन तंत्र में पाई जाने वाली एक लंबी टयूब है ।इसे बड़ी आंत भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक खास तरल पदार्थ को टयूब में भरा जाता है और टयूब के माध्यम से रेक्टम में डाला जाता है और दूसरे टयूब के माध्यम से शरीर से बाहर निकला जाता है। जिससे सारे टॉकसिक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं।

●उपवास रखना-उपवास अगर सही तरीके से किया जाये तो इससे भी शरीर डीटॉक्स होता है। ध्यान रखे कि उपवास में आप सिर्फ ताजे फल और जूस का इस्तेमाल करें। चीनी का सेवन करने से बचे ।सप्ताह में एक दिन अगर सही तरीक़े से से उपवास किया जाये तो ये शरीर को अन्दर से साफ करने में सहायक है।

●पंचकर्म- पंचकर्म चिकित्सा में पांच प्रक्रिया होती है। वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षम और अनुवासवस्ती ।इन पाँचों को संयोजन पंचकर्म कहते है। इन पाँचों का उद्देश्य हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकलना है। पंचकर्म करने से पहले किसी चिकित्सक की सलाह ले।

●प्राणायाम - फेफड़ों को डीटॉक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है प्राणायाम को अपने दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना चाहिए। प्राणायाम हमारे अन्दर के टोक्सिन निकल देता है ।प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास हमारे फेफड़ों को स्वस्थ रखता है। योग अभ्यास में भी काफी कि क्रिया है जो शरीर को अंदर से साफ करने में सहायक है । जैसे नेती, धैती,शंख प्रक्षालन । अगर आप कोई भी डीटॉक्स करे किसी विशेषज्ञ की सलाह ले के करे।

हमसे जुडे रहने के लिए (इंस्टाग्राम) instagram पर फ़ॉलो करें ritusinghfitness.

अवैध खनन मामले में 31 जनवरी तक रिपोर्ट प्रस्तुत करे राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: एनजीटी

एजेंसियां

एनजीटी ने अवैध विस्फोट और खनन के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आरएसपीसीबी) को 31 जनवरी, 2021 तक का समय दिया है मामला राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के पुर गांव का है जहां मेसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा अवैध विस्फोट और खनन किया गया था।

इस मामले में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 19 अगस्त, 2019 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें खनन के चलते आसपास की इमारतों में कंपन की बात को स्वीकार किया गया था। साथ ही रिपोर्ट में भवनों और अन्य जगहों पर पड़ने वाले असर की बात को स्वीकार किया था। इस रिपोर्ट में वहां पर 'टेल-टेल्स' (दरारों पर नजर रखने के लिए उपकरण) को लगाने की सलाह दी गई थी। इसके साथ ही खनन क्षेत्र को गांव से पहले ही अलग कर दिया गया है। साथ ही इस बाबत विशेषज्ञों की एक टीम को नियुक्त किया गया है।

इस मामले में 10 अक्टूबर, 2019 को एनजीटी ने भीलवाड़ा के जिला मजिस्ट्रेट को एक और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। 1 अक्टूबर 2020 को राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एक रिपोर्ट से पता चला है कि इस मामले में भीलवाड़ा के जिला अध्यक्ष से एक और रिपोर्ट मिली है, वर्तमान में, सीएसआईआर-सीबीआरआई, रुड़की की टीम ने 28 सितंबर से गांव पुर के घरों में भू-तकनीकी जांच और दरार की निगरानी का काम फिर से शुरू किया है जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। रिपोर्ट में अनुरोध किया गया कि इस मामले में जारी अंतरिम रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा जाए।

गोवा में कैनाकोना राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाये गये मैंग्रोव वृक्ष

एजेंसियां

राष्ट्रीय राजमार्ग -17 पर कैनाकोना राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास बनाने वाले प्रोजेक्ट प्रस्तावक ने उस क्षेत्र में मैन्ग्रोव के वृक्ष लगाए हैं। यह 1 सितंबर, 2019 को इस प्रोजेक्ट के लिए दी गई एनओसी की शर्तों में से एक शर्त थी।

गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि चूंकि परियोजना का एक भाग कछुओं के घोसलों के 300 से 500 मीटर के दायरे में है। ऐसे में वहां प्रकाश की व्यवस्था करने की अनुमति नहीं दी जा सकती साथ ही इस क्षेत्र में हॉर्न नहीं बजाया जा सकता। इसके साथ ही इस क्षेत्र में मैंग्रोव्स लगाने की भी शर्त रखी गई थी।

इस मामले में दत्तप्रसाद प्रभु गोनाकर ने आपत्ति की थी। इसलिए उनके सवालों के जवाब में जीसीजेडएमए ने एनजीटी के समक्ष एक हलफनामा दायर कर निम्नलिखित बातों का जवाब दिया है। तटीय क्षेत्र से जुड़े नियमों (सीआरजेड) की शर्तों को पूरा ने करने के बावजूद 28 सितंबर, 2015 को इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी। जिसमें कैनाकोना राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास के निर्माण को दी गई मंजूरी शामिल थी। इसके साथ ही इसमें तलपोना, गलगिबाग नदी और मैक्सिम क्रीक पर 3 पुलों के निर्माण को दी गई मंजूरी शामिल थी।

एनओसी में 1 सितंबर, 2017 को रखी गई शर्तों पर अमल नहीं किया गया था। जिसमें मैंग्रोव्स को काटना और माशेम पल पर ध्वनि और प्रकाश को रोकने के लिए अवरोध लगाना शामिल था। इसके साथ ही 30 अप्रैल, 2019 को गल्पीबाग नदी को अस्थायी तौर पर भरने के लिए जो शर्त रखी थी उसका पालन भी नहीं किया गया था।

इस मामले में जीसीजेडएमए ने एनजीटी के समक्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें जानकारी दी है कि यह परियोजना 29 नवंबर, 2019 को पूरी हो गई थी। इसके बाद भी जीसीजेडएमए माशीम पल के निर्माण कार्य पर नजर रखे हुए है। परियोजना के प्रस्तावक ने पुल के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए वहां से मिट्टी को हटाया था।

पराली धुंए की मार से दिल्ली बेहाल

एजेंसियां

केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक 12अक्टूबर को सुबह 304 अंकों के साथ 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया.

वायुगुणवत्ता के लिहाज से 12 अक्टूबर का दिन सीजन का सबसे खराब दिन रहा. दिल्ली-एनसीआर में हर सर्दियों में वायु प्रदूषण चरम तक पहुंच जाता है, जिससे यहां के निवासियों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से खतरा पैदा होता है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 36 प्रदूषण निगरानी स्टेशनों में से 19 स्टेशनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया, वहीं 14 स्टेशनों ने सूचकांक को 'खराब' श्रेणी में दर्ज किया, जबकि एक ने इसे 'मध्यम' श्रेणी रिकॉर्ड किया है.

उत्तर पश्चिम दिल्ली के वजीरपुर के पास के क्षेत्र में सर्वाधिक एक्यूआई 379 दर्ज किया गया, इसके बाद द्वारका सेक्टर 8 और मुंडका में एक्यूआई 364 रहा. वहीं लोधी रोड पर एक्यूआई 193 रहा, जो कि राजधानी का सबसे स्वच्छ क्षेत्र रहा. दिल्ली के पड़ोसी क्षेत्रों, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता बहुत खराब दर्ज की गई. वर्तमान में ग्रेटर नोएडा की हवा इन सभी में सबसे अधिक प्रदूषित है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, प्रदूषकों में वृद्धि, हवा की कम गति का यह परिणाम है. इसके अलावा पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में पराली की वजह से प्रदूषण और बढ़ रहा है. नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में पंजाब के अमृतसर और फिरोजपुर तथा हरियाणा के पटियाला, अम्बाला और कैथल के ऊपर खूब धुआं देखा गया.

मनीष सिसौदिया ने इस बीच केंद्र पर वार करते हुए कहा है कि पराली जलाने की समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर भारत की है, "दुर्भाग्यवश केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए कुछ नहीं किया. वह पूरा साल हाथ पर हाथ धरे बैठी रही. पूरा उत्तर भारत इसे भुगत रहा है."

हवा की गुणवत्ता को 0 से 500 के स्केल पर नापा जाता है. 0 से 50 के बीच एयर क्वॉलिटी को अच्छा माना जाता है, जबकि 300 से ऊपर यह बेहद खतरनाक होती है. दिल्ली में हर साल एक्यूआई 300 से ऊपर दर्ज किया जाता है जिस कारण वहां रहने वाले लोगों में तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं. साफ हवा में सांस लेने के लिए दिल्ली में ऑक्सीजन पार्लर तक का चलन चल चुका है.

मैक्सिको के किसानों ने बांध कब्जा कर अमेरिका का पानी रोका

एजेंसियां

मैक्सिको के किसानों ने पारंपरिक हथियारों से लैस होकर बोक्विला बांध कब्जा लिया और इस बांध से अमेरिका के राज्य टेक्सस में पानी को रोक दिया है। मैक्सिको के किसानों का कहना है कि हमारी सरकार अमेरिकी दबाव में हमारा पानी टैक्सास को दे रही है जबकि उनकी फसलों के लिए एक बूंद पानी बांध से अब तक नहीं छोड़ा गया है। इसलिए किसानों ने अगले एक माह तक बांध पर कब्जा कर अमेरिका को पानी देने से इंकार कर दिया है। इस मामले में किसानों को सबसे अधिक इस बात का दुख है कि जिस सरकार को उन्हें चुना है, वही उनका साथ न दे कर अमेरिका का साथ खड़ी दिख रही है

मेक्सिको और अमेरिका की अंतराष्ट्रीय सीमा पर स्थित बोक्विला बांध की सुरक्षा करने के लिए सैंकड़ों सैनिकों की तैनाती होने के बावजूद किसानों ने खुद को लाठी और अन्य देशी हथियारों से अपने को लैस हो कर सीमाक्षेत्र स्थित बांध पर कब्जा कर लिया। किसानों का कहना है की मेक्सिकन सरकार उनके हिस्से का पानी टेक्सास को भेज रही है जबकि उनकी फसलों के लिए कुछ भी पानी अब तक नहीं छोड़ा गया है। इसलिए उन्होने बांध पर एक महीने से भी ज्यादा समय के लिए कब्जा कर लिया है और अमेरिका को पानी देने से इंकार कर दिया है। किसानों की ओर इस काम में मदद करने वाले विक्टर वेलडर्रेन का कहना है कि यह किसानों के अस्तित्व की लड़ाई है, किसानों को जीवित रहने के लिए और अपनी फसल को तैयार कर अपने परिवार का पालनपोषण करने के लिए यह कदम उठाना जरूरी हो गया था।

अमेरिका और मेक्सिको पानी को लेकर लंबे समय से चल रहे तनाव ने अब हिंसा का रूप ले लिया है और मैक्सिकन किसानों को अपने ही राष्ट्रपति और वैश्विक महाशक्ति के खिलाफ खड़ा कर दिया है। दोनों देशों के बीच पानी के आदान-प्रदान पर बातचीत काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन बढ़ते तापमान और सूखे ने सीमा पर साझा नदियों को पहले से कहीं ज्यादा मूल्यवान बना दिया है, जिससे दोनों देशों का नदियों के पानी को लेकर अपने दांवपेच तेज हो गए हैं।

किसानों काा बांध पर कब्जा इस बात का उदाहरण है कि लोग जलवायु परिवर्तन से अपनी आजीविका की रक्षा करने के लिए कितना भी बड़ा भी कदम उठा सकते हैं। इस तरह के संघर्ष बढ़ते चरम मौसम के कारण और अधिक बढ़ सकते हैं।

पानी के अधिकार को लेकर अमेरिका और मेक्सिको के बीच एक दशक पुरानी संधि की गई थी। जिसमें कोलोराडो और रियो ग्रांडे नदियों के प्रवाह को साझा करने की बात कही गई है। अब तक दोनों देश एक-दूसरे को पानी भेजते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से अमेरिका को दिए जाने वाले पानी के मामले में मेक्सिको ने अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक से नहीं किया। यह संघर्ष इसी का नतीजा है। लेकिन मेक्सिको के चिहुआहुआ राज्य के लिए पिछले तीन दशकों में 2020 का वर्ष सबसे अधिक सूखे वर्षों में से एक है। इस सीमावर्ती राज्य से ही पानी भेजा जाता है, लेकिन सूखे के कारण वह नहीं भेज पा रहा है। ऐसे में जब मेक्सिको सरकार ने दबाव बनाया तो उस-के खिलाफ किसानों ने विद्रोह कर दिया। क्योंकि उन्हें लगा कि यदि पानी ही नहीं रहेगा तो अपनी खेती कैसे करेंगे। इस संबंध में एरिजोना विश्वविद्यालय में जल संसाधन नीति पढ़ाने वाले क्रिस्टोफ़र स्कॉट ने कहा, यह तनाव और इस प्रकार की प्रवृत्तियां पहले से ही हैं लेकिन वास्तव में यह सब जलवायु परिवर्तन के कारण और बढ़ गईं हैं। उन्होंने किसानों की इस लड़ाई को उनके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई करार दी क्योंकि जब पानी ही नहीं रहेगा तो जीवन, खेती और न ही कोई ग्रामीण समुदाय ही बचेगा।

तीन करोड़ लोगों पर आर्सेनिकयुक्त जल का खतरा

एजेंसियां

देश में आर्सेनिकयुक्त पानी के सेवन से हो रहे शारीरिक विकृतियों के अलावा अन्य स्वास्थ्य समस्यायें चुनौती बनते जा रही हैं। और इसकी रोक थाम में कोई सुधार भी नजर नहीं आ रहा है।

आंकड़ों के अनुसार 2015 में 1,800 बस्तियां आर्सेनिक से प्रभावित थी जो 2017 में बढ़कर 4,421 हो गई भारत में 1.8 से 3 करोड़ लोगों पर आर्सेनिक का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। जिसके लिए पीने का पानी जिम्मेवार है। देश की एक बड़ी आबादी आज भी पीने के पानी के लिए भूमिगत जल पर निर्भर है। आज भी भारत में भूजल पीने के पानी और सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देश में धीरे-धीरे न केवल जिसकी मात्रा में कमी आ रही है, साथ ही इसकी गुणवत्ता में भी गिरावट आती जा रही है। जिसके लिए काफी हद तक आर्सेनिक भी जिम्मेवार है। यह जानकारी हाल ही में किए एक शोध में सामने आई है, जोकि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायर्नमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित हुआ है। जिसे मैनचेस्टर, पटना और ज्यूरिख के शोधकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।

इस शोध से यह भी पता चला है कि देश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में भूजल के अंदर उच्च मात्रा में आर्सेनिक मौजूद है, जोकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शोध के अनुसार उत्तर भारत में आर्सेनिक की मात्रा खतरनाक स्तर पर है। इसके साथ ही देश के कई अन्य इलाकों में आर्सेनिक की मात्रा तय मानकों से कहीं ज्यादा है। जिसमें दक्षिण-पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्से शामिल हैं। शोध के अनुसार इससे पहले इन क्षेत्रों में आर्सेनिक के सबूत नहीं मिले थे।

आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों में दर्ज की गई 145 फीसदी की वृद्धि

इससे पहले 18 सितम्बर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संसद में दिए आंकड़ें भी इस बात की पुष्टि करते हैं। इन आंकड़ों के अनुसार 2015 में 1,800 बस्तियां आर्सेनिक से प्रभावित थी जो 2017 में बढ़कर 4,421 हो गई हैं। जिसका मतलब है कि पिछले पांच वर्षों में उनमें 145 फीसदी की वृद्धि देखी गई है।

यह बस्तियां मुख्य रूप से असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हैं। झारखंड, जिसमें 2015 में ऐसी कोई बस्ती नहीं थी, अब वहां की दो बस्तियां आर्सेनिक प्रभावित हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में असम में सबसे ज्यादा बस्तियां आर्सेनिक से ग्रस्त हैं जिनकी संख्या 1853 है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर है जहां 1,383 बस्तियां इससे पीड़ित हैं।

वहीं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के 63 जिलों के भूजल में मानक से अधिक फ्लोराइड, 25 जिलों के भूमिगत जल में आर्सेनिक तथा 18 जिलों के भूजल में फ्लोराइड एवं आर्सेनिक दोनों मानक से कई गुना अधिक है। यह जानकारी वाटर एण्ड सेनिटेशन मिशन, उप्र द्वारा एक आरटीआई के जबाव में सामने आई थी। जबकि एनजीटी में सबमिट एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 707 बस्तियां आर्सेनिक प्रभावित हैं। जबकि बिहार के 18 जिलों के भूगर्भ जल में आर्सेनिक का जहर फैला हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक बिहार के करीब 1 करोड़ लोग आर्सेनिक युक्त पानी पी रहे हैं। कई इलाकों में तो पानी में आर्सेनिक की मात्रा 1,000 पीपीबी से ज्यादा है, जो सामान्य से 20 गुना अधिक है।

पानी में मौजूद आर्सेनिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। इससे कैंसर, हृदय रोग और यहां तक की असमय मृत्यु भी हो सकती है। यह समस्या अत्यंत गंभीर है, इसके बावजूद देश में अभी भी पीने के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिकांश कुओं में मौजूद आर्सेनिक की जांच नहीं हुई है। लेकिन इतने विस्तृत इलाके में इसे कर पाना आसान नहीं है यही वजह है कि इस शोध में मॉडलिंग की मदद से इसकी जांच की गई है।

शोधकर्ताओं के अनुसार यह मॉडलिंग उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। जिस वजह से इसकी मदद से गहरे कुओं के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना मुश्किल है। ऐसे में इन क्षेत्रों में व्यापक जांच जरुरी हो जाती है, जिससे स्थिति की सही जानकारी प्राप्त हो सके। इसके साथ ही शोध पीने के लिए उपयोग किये जाने वाले कुओं की भी रैंडम जांच की सिफारिश करता है। जिसकी मदद से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को सीमित किया जा सके।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

● **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।